

आर्थिक अंतर्दृष्टि: जयपुरिया संस्थान, इंदौर में बजट 2025 के बाद का विश्लेषण



इंदौर। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर ने केंद्रीय बजट 2025 पर एक विचारोत्तेजक सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत इंस्टीट्यूट को हाल ही में एसोसिएशन टू एडवांस कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस द्वारा मान्यता प्राप्त होने के जश्न से हुई। इसके बाद संस्थान के निदेशक डॉ. दीपंकर चक्रवर्ती ने स्वागत भाषण दिया। इस सत्र में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और उद्योग विशेषज्ञों के एक पैनल ने बजट और 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के साथ इसकी संरचना का गहन विश्लेषण किया। इस चर्चा का संचालन डॉ. घनश्याम पांडे ने किया, जिन्होंने इस सत्र को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रमुख वक्ताओं में प्रो. आर.एस. देशपांडे (पूर्व निदेशक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलुरु एवं पूर्व कुलपति, बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु), डॉ. पी.एस. बिर्थल (निदेशक, आईसीएआर-एनआईएपी), डॉ. एस.पी. शर्मा (मुख्य अर्थशास्त्री, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री), और श्री शिशिर सिन्हा (प्रसिद्ध आर्थिक पत्रकार, द हिंदू बिजनेस लाइन) शामिल थे। उन्होंने बजट के बाद की स्थिति का आर्थिक विकास, नीतिगत प्रभाव और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में मूल्यांकन किया। चर्चा में कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निवेश, निर्यात, और मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था में भूमिका जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया। वित्तीय नीतियों, मुद्रास्फूर्ति, पूंजीगत व्यय, और बजटीय प्रावधानों के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभावों पर भी चर्चा हुई। एमएसएमई और मध्यम वर्ग को आर्थिक प्रगति के प्रमुख प्रेरक तत्वों के रूप में समर्थन देने पर विशेष जोर दिया गया।

प्रो. देशपांडे ने बजट के महत्व को भारत की भू-राजनीतिक स्थिति और घरेलू आर्थिक आवश्यकताओं की दृष्टि से विश्लेषित किया। उन्होंने भारत की वैश्विक छवि को एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में रेखांकित किया और आर्थिक सर्वेक्षण में उजागर मुद्दों, जैसे बेरोजगारी, वित्तीय अनुशासन, रुपये का अवमूल्यन और विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि पर चर्चा की। डॉ. बिर्थल ने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए अनुसंधान में अधिक निवेश, प्रभावी भूमि उपयोग योजना और विविधीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पंजाब में जल संकट की गंभीरता को रेखांकित किया और जल संसाधन प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा, उन्होंने कृषि में बाजार खुफिया तंत्र की कमी और सब्सिडी के रणनीतिक पुनर्गठन की आवश्यकता पर भी ध्यान दिलाया।

जयपुरिया संस्थान में बजट विश्लेषण

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9009585701

जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने केंद्रीय बजट 2025 पर एक विचारोत्तेजक सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और उद्योग विशेषज्ञों के एक पैनल ने बजट और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के साथ इसकी संरचना का गहन विश्लेषण किया। इस चर्चा का संचालन डॉ. घनश्याम पांडे ने किया, जिन्होंने इस सत्र को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख वक्ताओं में प्रो. आरएस



देशपांडे (पूर्व निदेशक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलुरु एवं पूर्व कुलपति, बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु), डॉ. पीएस बिर्थल (निदेशक, आईसीएआर-एनआईएपी), डॉ. एस.पी. शर्मा (मुख्य अर्थशास्त्री, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) और शिशिर सिन्हा (प्रसिद्ध आर्थिक पत्रकार, द हिंदू बिजनेस

लाइन) शामिल थे। उन्होंने बजट के बाद की स्थिति का आर्थिक विकास, नीतिगत प्रभाव और विभिन्न क्षेत्रों के विकास के संदर्भ में मूल्यांकन किया। प्रो. देशपांडे ने बजट के महत्व को भारत की भू-राजनीतिक स्थिति और घरेलू आर्थिक आवश्यकताओं की दृष्टि से विश्लेषित किया। उन्होंने भारत की वैश्विक छवि को एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में रेखांकित किया। डॉ. बिर्थल ने कृषि क्षेत्र की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए अनुसंधान में अधिक निवेश, प्रभावी भूमि उपयोग योजना और विविधीकरण की आवश्यकता पर बल दिया।

NAV BHARAT 18/2/25

RAJ EXPRESS 18/2/25

जयपुरिया संस्थान, इंदौर में बजट 2025 के बाद का विश्लेषण

18/2 Nav Bharat

अपना शहर

एक नजर में

जयपुरिया संस्थान में बजट 2025 के बाद का विश्लेषण

इंदौर। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर ने केंद्रीय बजट 2025 पर एक विचारोत्तेजक सत्र का आयोजन किया। संस्थान के निदेशक डॉ. दीपंकर चक्रवर्ती ने स्वागत भाषण दिया। इस सत्र में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और उद्योग विशेषज्ञों के एक पैनल ने बजट और 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के साथ इसकी संरचना का गहन विश्लेषण किया। इस चर्चा का संचालन डॉ. घनश्याम पांडे ने किया। प्रमुख वक्ताओं में प्रो. आर.एस. देशपांडे (पूर्व निदेशक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलुरु एवं पूर्व कुलपति, बी.आर. अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु), डॉ. पी.एस. बिर्थल (निदेशक, आईसीएआर-एनआईएपी), डॉ. एस.पी. शर्मा (मुख्य अर्थशास्त्री, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) शिशिर सिन्हा आर्थिक पत्रकार शामिल थे।

इंदौर। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर ने केंद्रीय बजट 2025 पर एक विचारोत्तेजक सत्र का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत इंस्टीट्यूट को हाल ही में एसोसिएशन टू एडवांस कॉलेजिएट स्कूल्स ऑफ बिजनेस (एससीएसबी) द्वारा मान्यता प्राप्त होने के जश्न से हुई। इसके बाद संस्थान के निदेशक डॉ. दीपंकर चक्रवर्ती ने स्वागत भाषण दिया। इस सत्र में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और उद्योग विशेषज्ञों के एक पैनल ने बजट और 'विकसित भारत 2047' के दृष्टिकोण के साथ इसकी संरचना का गहन विश्लेषण किया। इस चर्चा का संचालन डॉ. घनश्याम पांडे ने किया। चर्चा में कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), निवेश, निर्यात, और मध्यम वर्ग की अर्थव्यवस्था में भूमिका जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया।